संख्या-47/2026/1122/78-1-2026-85/2026

प्रेषक,

अर्जुन देव भारती,
संयुक्त सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

उद्योग निदेशक,
कानपुर, उ0प्र0।

आई0टी0 एवं इलेक्ट्रानिक्स अनु0-1 लखनऊ: दिनांक: 16-10-2026

विषय: वित्तीय वर्ष 2026-27 में राज्य आय-व्ययक की अनुदान संख्या-007 के अन्तर्गत उत्तर प्रदेश आई.टी. सदन की स्थापना हेतु पूंजीगत पक्ष में प्राविधानित रू0 5000.00 लाख के सापेक्ष समग्र धनराशि रु0 5000.00 लाख की वित्तीय स्वीकृति जारी कराने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक प्रबन्धक यूपीडेस्को के पत्र संख्या-D/26-27/2480, दिनांक 19-09-2026 द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्ताव के संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2026-27 के पूंजीगत के राज्य आय-व्ययक की अनुदान संख्या-007-उद्योग (भारी एवं मध्यम उद्योग) के लेखा शीर्ष 4859-दूरसंचार तथा इलेक्ट्रानिक उद्योगों परिव्यय-02-इलेक्ट्रॉनिक-800-अन्य निवेश-20-उत्तर प्रदेश आईटी सदन की स्थापना-60-भूमि क्रय के मद में रू0 5000.00 लाख के सापेक्ष रू0 5000.00 लाख (रूपये पांच हजार लाख मात्र) को निदेशक उद्योग के निवर्तन पर रखे जाने तथा प्रबन्ध निदेशक, उत्तर प्रदेश डेवलपमेंट सिस्टम्स कारपोरेशन लि0 लखनऊ द्वारा आहरित कर निम्नलिखित शर्तों के अधीन व्यय करने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

(1) उक्त स्वीकृत धनराशि के आहरण हेतु वित्तीय नियम संग्रह खण्ड-5, भाग-1 के प्रपत्र संख्या- 6(ए)(संशोधित) द्वारा निर्धारित प्रपत्र पर प्रबन्ध निदेशक, उत्तर प्रदेश डेवलपमेंट सिस्टम्स कारपोरेशन लि0 लखनऊ द्वारा बिल बनाकर उसे संयुक्त निदेशक, उद्योग, लखनऊ मण्डल,
लखनऊ को प्रतिहस्ताक्षर हेतु प्रस्तुत किया जायेगा। उद्योग निदेशक, उ0प्र0 कानपुर, आहरण तथा वितरण का पूरा लेखा-जोखा अपने यहां भी रखेंगे।

(2) उद्योग निदेशक द्वारा वित्त विभाग के आदेश संक्ष्या-बी-1-417/10-2013-16/94, दिनांक 26 फरवरी, 2013 में दी गयी प्रक्रियानुसार सेंट्रल सर्वर के माध्यम से सम्बन्धित कोषागार को बजट आवंटन भेजे जाने की कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी।

(3) उक्त स्वीकृत धनराशि का व्यय केवल उसी मद में किया जायेगा जिसके लिए स्वीकृत किया जा रहा है।

(4) उक्त स्वीकृत धनराशि का व्यय वित्तीय वर्ष 2026-27 में ही सुनिश्चित किया जायेगा तथा धनराशि के व्यय के उपरान्त उत्तर प्रदेश डेवलपमेंट सिस्टम्स कारपोरेशन लि0 लखनऊ द्वारा उपयोगिता प्रमाण-पत्र महालेखाकार, उ0प्र0, उद्योग निदेशक, कानपुर तथा शासन को उपलब्ध कराया जायेगा।

(5) स्वीकृत धनराशि का आहरण राज्यकोष से तात्कालिक आवश्यकता के आधार पर ही किया जायेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

(6) किसी परिस्थिति में धनराशि को पूर्व से आहरित करके एकमुश्त पी0एल0ए0/बैंक खाते/अन्य किसी खाते में नही रखा जायेगा।

(7) स्वीकृत धनराशि व्यय किये जाने के पूर्व वित्त(आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय-ज्ञाप दिनांक 28-03-2026 द्वारा दिशा-निर्देशों को पूर्णतया अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(8) किसी भी वित्तीय अनियमितता के लिए उत्तर प्रदेश डेवलपमेंट सिस्टम्स कारपोरेशन लि0 लखनऊ उत्तरदायी होंगे।

(9) आहरित धनराशि के सापेक्ष उपयोगिता प्रमाण-पत्र यथासमय शासन को उपलब्ध कराया जायेगा।

2- इस संबंध में होने वाला व्यय रुपये 50,00,00,000 (रुपये पचास करोड़ मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2026-27 के आय-व्ययक मे **अनुदान संख्या** 007 **लेखा शीर्षक** 4859028002000 उत्तर प्रदेश आई. टी. सदन की स्थापना **मानक मद** 60 भूमि क्रय के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश अशासकीय संख्या-E-6-55-X-2026-27, दिनांक 14-10-2026 मे प्राप्त वित्त विभाग की सहमति से निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,
अर्जुन देव भारती
संयुक्त सचिव।

संख्या एवं दिनांक तदैव।

उपर्युक्त की प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास आयुक्त, उ0प्र0 शासन।
2- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), प्रथम एवं द्वितीय, उ0प्र0 प्रयागराज।
3- प्रधान महालेखाकार(लेखा-परीक्षा) प्रथम एवं द्वितीय, उ0प्र0 प्रयागराज ।
4- निदेशक, कोषागार, जवाहर भवन लखनऊ।
5- निदेशक, वित्तीय सांख्यकीय निदेशालय, जवाहर भवन लखनऊ।
6- मुख्य कोषाधिकारी, कलेक्ट्रेट लखनऊ, उ0प्र0।
7- संयुक्त निदेशक, उद्योग लखनऊ मण्डल, लखनऊ।
8- प्रबन्ध निदेशक, उत्तर प्रदेश डेवलपमेंट सिस्टम्स कारपोरेशन लि0 लखनऊ।
9- राज्य समन्वयक सेन्टर फार ई-गवर्नेन्स लखनऊ।
10- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-6/नियोजन अनु0-4
11- वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/लघु उद्योग अनु0-3/औद्योगिक विकास अनु0-2
12- आई0टी0 एवं इलेक्ट्रानिक्स अनुभाग-2, उ0प्र0 शासन।
13- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
अर्जुन देव भारती
संयुक्त सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।